

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुध,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 11 अप्रैल, 2018

विषय- पुरकल यूथ डवलपमेंट सोसाइटी को शिक्षण संस्थान के प्रयोजनार्थ ग्राम रिखोली, परगना पछवादून, जिला देहरादून में 1.183 है० भूमि क्रय करने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2152/12ए-280/(2014-2017)डी०एल०आ०सी०-2017, दिनांक 18 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "पुरकल यूथ डवलपमेंट सोसाइटी" के पक्ष में शिक्षण संस्थान के प्रयोजनार्थ ग्राम रिखोली परगना पछवादून, जिला देहरादून के खाता संख्या-4 पर खसरा नं०-654ग मि०/0.3525 है०, खाता संख्या-102 के खसरा नं०-654ग मि०/0.3525 है०, खाता संख्या-129 के खसरा नं०-654क/0.2760 है० तथा खाता संख्या-130 के खसरा नं०-654ख/0.2020 है० कुल-1.183 है० भूमि क्रय करने की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा-154(4)(3)(क)(II) के अन्तर्गत क्रय हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- संस्था द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का आवश्यक विवरण/संबंधित अभिलेख जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त कर भूमि क्रय की अनुमति के संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी।
- 4- क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण

करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

- 5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 6- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 7- शासन द्वारा दी गई भूमिक्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 8- प्रस्तावित भूमि का उपयोग संस्था द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु ही किया जायेगा तथा इससे भिन्न कार्य हेतु यदि भूमि का उपयोग किया जाता है तो उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी एवं संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।
- 9- किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 10- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 11- नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियाँ प्राप्त कर ली जायेंगी।
- 12- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 13- उक्त आवंटित भूमि पर निर्मित भवन निर्धारित माकों, भूकम्प विरोधी, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हारवेस्टिंग, सौर ऊर्जा आदि सुविधाओं को सुनिश्चित किया जायेगा।
- 14- सम्बन्धित संस्था द्वारा प्रस्तावित योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) से शून्य आधारित (Zero based) अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 15- सम्बन्धित संस्था द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 16- जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के मध्य व किनारे चेक रोड, नाला तथा राज्य सरकार की अवशेष भूमि आदि होने अथवा न होने की स्पष्ट सूचना/विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- 17- संस्था के द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के मानकों एवम् अन्य प्रभावी नियमों/विनियमों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की घोषणा पत्र दिया जायेगा।

18- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से जिसे शासन उचित समझता है, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव।

संख्या-344/XVIII(II)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, देहरादून।
- 4- जे०के० स्वामी, सचिव, पुरकुल यूथ डवलपमेंट सोसाइटी, पुरकल गांव, भगवंतपुर, देहरादून।
- 5- निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 6- प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी०एम० मिश्र)
अपर सचिव।